भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .603

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

श्रीनगर रिंग रोड के लिए भूमि का अधिग्रहण

603. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 600 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाली श्रीनगर रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में शिकायतें आ रही हैं क्योंकि मुआवजे की गणना अप्रचलित जम्मू-कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1934 के अंतर्गत की जा रही है और यदि हां, तो निरस्त कानूनों का उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या फलदार वृक्षों के लिए मुआवजे की गणना 1996 की दरों के आधार पर की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान बाजार मूल्यों से काफी कम भुगतान प्राप्त होता है और यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 को कार्यान्वित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उचित मुआवजे के बिना फलों के पेड़ों को अनधिकृत रूप से उखाड़ने, जैसा कि बडगाम जिले के वाथूरा और गुडा सथू गांवों के संबंध में रिपोर्ट आई है, से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्तमान में, श्रीनगर रिंग रोड चरण 2 और चरण 2ए के लिए भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) अधिनियम, 1956 के तहत किया जा रहा है, जिसमें मुआवजे का निर्धारण **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** के अनुसार किया जाता है। हालांकि, श्रीनगर रिंग रोड के चरण-I के लिए भूमि अधिग्रहण 2017-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1934 के अनुसार जम्मू और कश्मीर में तत्कालीन लागू विधिक स्थिति के अनुसार किया गया था।

(ख) संरचनाओं, पेड़ों, ट्यूबवेल आदि जैसी परिसंपत्तियों के लिए मुआवजे का आकलन भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्कालीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के मानदंडों के अनुसार किया जाता है। विशेषकर, फलदार पेड़ों के लिए मुआवजे का आकलन स्थानीय बागवानी अधिकारियों द्वारा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ग) जैसा कि उपरोक्त (क) में है।

(घ) श्रीनगर रिंग रोड के अंतर्गत आने वाले बड़गाम जिले के वाथूरा और गुड्सथू गांवों के लिए संपत्ति सहित भूमि अधिग्रहण का अधिनिर्णय जारी कर दिया गया है। सामान्य तौर पर सही मालिकों को मुआवजा वितरित कर दिया गया है, हालांकि, विवादित मामलों में मुआवजा जिला न्यायालय में जमा कर दिया गया है। रिंग रोड के निर्माण के लिए भूमि का अधिकार कानून के अनुसार सीएएलए द्वारा एनएचएआई को सौंपा जा रहा है।

*****